

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वंचित वर्गों का सामाजिक उत्थान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत पात्र विधवाओं की बेटियों को 27 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार राज्य से बाहर सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को किराया सा पीजी आवास शुल्क के लिए अधिकतम दस महीनों तक प्रतिमाह 3 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग की 5 सौ 4 छात्राएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से इस वर्ष 3 फरवरी तक करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

कुलदीप पठानिया

मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आज सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सेरी मंच से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक करीब 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को प्रदेश का भाग्य सुधारने के लिए चुना था लेकिन सरकार जनता को राहत देने के बजाय सड़कों पर उतर कर धरने और प्रदर्शन की राजनीति कर रही है। राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2025 के बीच प्रदेश को 89 हजार करोड़ की सहायता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से इतनी सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी और सरकार नये-नये कर लगा कर जनता पर बोझ डाल रही है।

कार्यशाला

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन में उद्योग विभाग द्वारा रैंप कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला की महिला उद्यमियों ने बढ़चढ़ का हिस्सा लिया और अपने व्यवसाय को नई दिशा देने के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला की प्रभारी कृतिका शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम महिलाओं को फंडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई।

नगर निगम

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6 सौ 88 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले वर्ष ये बजट एक सौ 88 करोड़ रुपए का था। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला शहर में 26 चिन्हित स्थानों पर फूड वैन स्थापित किए जाएंगे, ताकि बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अलावा उन्होंने शिमला के कोर एरिया में ई कार्ट चलाने और शहर के हर वार्ड में पार्किंग निर्माण की घोषणा की।

निरीक्षण

खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव संदीप कदम ने अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान आज कुल्लू जिला में पीएम श्री योजना के तहत संचालित विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बंदरोल, राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला लोअरविंग कुल्लू और पीएम श्री राजकीय प्राथमिक पाठशाला मौहल का निरीक्षण कर शैक्षणिक व आधारभूत विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।
